दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 28 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 61

महत्वपूर्ण एवं खास

5वें वित्त आयोग के कार्यकाल और कवरेज के विस्तार पर दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मिली मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है। कार्यकाल के विस्तार से वित्त आयोग 2020 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने तथा सुधारों और नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलनीय अनुमानों की जांच पड़ताल करने में सक्षम होगा। आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण लागू प्रतिबंधों के कारण अभी हाल में राज्यों की अपनी यात्रा पूरी की है। इससे राज्यों की जरूरतों के व्यापक आकलन पर प्रभाव पड़ा है।

स्पेन में होने वाले संरा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भारतीय रुख को मंजूरी दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैड्रिड, स्पेन में 2 से 13 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले (चिली की अध्यक्षता में) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए 25वें कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (सीओपी) में आज भारत की बातचीत के रूख को स्वीकृति दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। सीओपी 25 एक अहम सम्मेलन है जिसमें देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2020 से पहले की अवधि से निकलकर पेरिस समझौते के तहत 2020 के बाद की अवधि में प्रवेश की तैयारी करते हैं। भारत का रूख जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन-यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के सिद्धांतों एवं प्रावधानों खासकर स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमता (सीबीडीआर-आरसी) से संचालित होगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के बीच हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला उद्यमियों का राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निफ्टेम, कुंडली (सोनीपत, हरियाणा) इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगा और इसे आयोजित करेगा। निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्थान है। महोत्सव का उद्देश्य भारतीय महिला उद्यमियों और किसानों को खरीददारों के साथ जोड़ना है। इससे महिला उद्यमियों और किसानों के वित्तीय समावेश में मदद मिलेगी और भारत में जैविक खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। समझौता ज्ञापन के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय, निफ्टेम के कुलपति को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन राशि हस्तांतरित करेगा। कुलपति ने वार्षिक महोत्सव को आयोजित करने की सहमति जताई है।

मंत्रिमंडल ने अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट वर्ष 2019-20 के लिए खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी।

सरकार ने पिछले वर्ष के सामान जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के विस्तार को बनाए रखा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में की जानी चाहिए।

चीनी की पैकेजिंग जूट की बोरियों में करने से जूट उद्योग को लाभ मिलेगा। निर्णय में यह भी कहा गया है कि पैकेजिंग के लिए जूट बोरियों का 10 प्रतिशत जीईएम पोर्टल पर नीलामी के जरिए प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस मंजूरी से देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए जूट क्षेत्र पर निर्भर है। सरकार जूट क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है- कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना, जूट क्षेत्र का विविधीकरण और जूट उत्पादों के लिए मांग को बढ़ावा देना।

जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है, जो खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए प्रति वर्ष 7,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जूट की बोरियां खरीदती हैं। जूट क्षेत्र में मांग को बनाए रखने के लिए तथा श्रमिकों और किसानों की आजीविका को समर्थन प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है।

कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जूट आईसीएआरई लागू किया गया था। इसके जरिए सरकार लगभग दो लाख जूट किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत बेहतर तरीकों जैसे- सीड ड्रिल के माध्यम से पंक्ति में बीज रोपना, व्हील-होइंग और नेल-वीडर के उपयोग से खत-पतवार प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणीकृत बीजों का वितरण और सूक्ष्म जीवों के सहारे सड़ाना/जूट रेशे को तैयार करना। इन हस्ताक्षेपों से कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है और जूट किसानों की आय में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि हुई है।

इस संबंध में जूट किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए जेसीआई को 2018-19 से प्रारंभ होने वाले वर्ष समेत दो वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुदान दिया गया है। जेसीआई इस धन राशि का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए करेगा और इस प्रकार जूट क्षेत्र में मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगाः गोयल

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के आर्थिक विकास की रणनीति के बारे में विचार-विमर्श के लिए आयोजित 'कश्मीरोनोमिक्स' सम्मेलन में कहा कि इन दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इससे वहां औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उद्योगजगत एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री एवं सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेलमंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय और भी अधिक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, व्यापार विकास केन्द्रों, आधुनिक महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना करने तथा और भी अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने की योजना बना रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वित होने से दोनों केन्द्रशासित प्रदेश अगले 10 वर्षों में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। गोयल ने कहा कि पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, पनबिजली और सौर बिजली अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र हैं, किन्तु अब तक इनका लाभ नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के बल पर जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकता है।

मानव तस्करी रोकने भारत-म्यांमार में हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध को और मजबूत करना एवं मानव तस्करी को रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना।

मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाना और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना। दोनों देशों में मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना। आप्रवासन एवं सीमा नियंत्रण सहयोग को मजबूत करना और मानव तस्करी रोकने के लिए संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के साथ रणनीति का क्रियान्वयन। मानव तस्करी रोकने की कोशिशों के तहत कार्य समूह/कार्यबल का गठन करना। मानव तस्करों एवं तस्करी के शिकार लोगों के आंकड़े जुटाना और भारत एवं म्यांमार के तय केंद्र बिंदुओं के जरिए सूचना का आदान-प्रदान करना। दोनों देशों से जुड़ी एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना। तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाना और स्वदेश वापस भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करना और उसका पालन करना। मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलता बन गई है। मानव तस्करी की जटिल प्रकृति की वजह से घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। मानव तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत है।भारत और म्यांमार के बीच सीमा नियंत्रण एजेंसियों और संचार के विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग मानव तस्करी रोकने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

भारत, सऊदी अरब के बीच मादक पदार्थ की बिक्री और तस्करी रोकने पर हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।

समझौता ज्ञापन से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण सम्मेलन द्वारा परिभाषित नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों एवं प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री एवं तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों के उत्पादकों, तस्करों एवं अवैध विक्रेताओं की संदिग्ध गतिविधियों, आग्रह करने पर एनडीपीसी की अवैध बिक्री के विवरण और नशीली दवाइयों संबंधित आरोप में गिरफ्तार विक्रेताओं के वित्तीय हालात से संबंधित जानकारियां साझा करने का प्रावधान है।

समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार दूसरे देश के नागरिकों के विवरण के साथ अधिसूचित करने का और गिरफ्तार व्यक्ति को दूतावास संबंधी मदद मुहैया कराने का प्रावधान है।

समझौता ज्ञापन के तहत दोनों में से किसी भी देश के अंदर बरामद की गई नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण और नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों के बारे में आंकड़ा/सूचना साझा करने का प्रावधान है।

अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री एक वैश्विक अवैध व्यापार बन गई है। नशीले पदार्थों का बड़े स्तर पर उत्पादन और विभिन्न सरल मार्गों खासकर अफगानिस्तान के जरिए इसका प्रसार बढ़ने से युवाओं के बीच इसका उपभोग ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और समाज का अपराधीकरण बढ़ा है। नशीले पदार्थों की बिक्री से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बगावत और आतंकवाद के लिए धन मुहैया होता है।

आसमान में भारत की आंख कार्टोसेट-3 सैटेलाइट लांच

» इसरो ने रचा इतिहास

श्रीहरिकोटा (आरएनएस)। आसमान में भारत की आंख कहे जाने वाले कार्टोसेट उपग्रहों की सीरीज की नवीनतम तीसरी पीढ़ी के उपग्रह पीएसएलवी-सी47 कार्टोसेट-3 को आज प्रक्षेपित कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को सुबह 9: 28 मिनट पर कार्टोसैट-3 को लॉन्च किया। इसके लिए इसरो चीफ के. सिवन श्रीहरिकोटा मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। उनके साथ मिशन के इंजिनियर्स और इसरो के टॉप साइंटिस्ट मौजूद हैं। -कार्टोसैट-3 को भारत की आंख भी कहा जा रहा है क्योंकि इससे बड़े स्तर पर मैपिंग की

जा सकेगी जिससे शहरों की प्लानिंग और ग्रामीण इलाकों के संसाधनों का प्रबंधन भी किया जा सकेगा।

यह कार्टोसैट श्रृंखला का नौवां उपग्रह है जिसे यहां से 120 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। पीएसएलवी-सी47 की यह 49वीं उड़ान है जो कार्टोसैट-3 के साथ अमेरिका के वाणिज्यिक उद्देश्य वाले 13 छोटे उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का बेहद चुस्त और उन्नत उपग्रह है जिसमें हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने की क्षमता है। इसका भार 1,625 किलोग्राम है। यह पीएसएलवी एक्सएल विन्यास का है। इसका आशय है कि इसमें छह ठोस ईंधन वाली स्ट्रैप-ऑन मोटरें लगी हैं। अमेरिकी नैनो उपग्रहों में से 12 को फ्लॉक-4पी के रूप में नामित किया गया है। यह सभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 13वां उपग्रह एक कम्युनिकेशन टेस्ट बेड सैटेलाइट है, जिसका नाम मेशबेड है। यह उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाले फोटो क्लिक करेगा। ये ठोस और तरल ईंधन के जरिए संचालित किया जाता है।

पीएम मोदी ने दी पीएसएलवी-सी-47 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की टीम को बधाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह और अमरीका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों सहित पीएसएलवी-सी-47 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह और अमरीका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों सहित पीएसएलवी-सी-47 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्नत कार्टोसैट-3 से हमारी हाई रिजोल्यूशन क्षमता बढ़ेगी। इसरो ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है।'

तिहाड़ में चिदंबरम से मिले राहुल और प्रियंका

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को यहां तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद चिदंबरम इसी जेल में हैं। इससे लगभग एक महीने पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तिहाड़ में चिदंबरम से मुलाकात की थी।

पार्टी नेताओं के अनुसार, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित चिदंबरम का पिछले तीन महीनों में लगभग 10 किलोग्राम वजन कम हो गया है।

वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान चिदंबरम द्वारा आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में कथित अनियमितता के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रही है।

पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और पांच सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

» कई जिलों में स्कूल-कालेज बंद

किन्नौर (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में मंगलवार रात से हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके अलावा लाहुल व कुल्लू की पहाड़ियों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। जिला कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है, जिससे समूची घाटी ठंड की चपेट में है।

बदस्तूर जारी इस बर्फबारी के चलते कई इलाकों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। देर

रात से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी जारी है। किन्नौर के निचार, कल्पा, पूह ब्लॉक में जिला प्रशासन ने दो दिनों के लिए स्कूलों की छुटियां घोषित कर दी हैं मौसम को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। उधर, भारी बर्फबारी के चलते कई इलाकों में बिजली और टेलीफोन सेवा ठप है जिससे दूरदराज के इलाकों में लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है।

किन्नौर में बीती रात से हल्की बारिश हो रही थी जिसके चलते पूरा इलाका ठंड की चपेट में आ गया। लेकिन आधी रात के बाद से मौसम का मिजाज बिल्कुल खराब हो गया और बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढंक गया है।

बता दें कि किन्नौर की पहाड़ियों पर महीनेभर से बर्फबारी हो रही थी और निचले इलाकों में सिर्फ बर्फबारी हो रही थी। लेकिन अब निचले इलाकों में भी बर्फबारी के चलते पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। सारे जलश्रोत जम गए हैं और पैदल मार्ग भी बर्फबारी के चलते बंद हो चुके हैं।

गडकरी ने किया नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन

मानेसर (आरएनएस)। केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉ (आईसीएटी) में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया।

उन्होंने वैकल्पिक ईंधन प्रणाली तथा ई-मोबिलिटी जैसे प्रासंगिक विषयों पर सम्मेलन के आयोजन के लिए आईसीएटी को बधाई दी। उन्होंने कृषि क्षेत्र को ऑटोमोबिल क्षेत्र से जोड़ने के महत्व को दोहराया और कहा कि जैव डीजल, कृषि तथा ऑटो इंडस्ट्री का भाग्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि जैव डीजल के लिए अखाद्य तेल के उत्पादन से देश के कृषि आधार को समर्थन दिया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ऑटोमोटिव उद्योग को महत्वपूर्ण मानती है और कारगर नीतियों से उद्योग को समर्थन देना चाहती है। तीन दिन का यह सम्मेलन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉका सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत सहित 15 देशों के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉके विशेषज्ञ 120 तकनीकी शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

इस अवसर पर आईसीएटी के

निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि आईसीएटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों की श्रृंखला में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन 2019 पहला है। दिनेश त्यागी ने कहा कि इससे देश में 125 वर्षों से उपयोग किए जाने वाले आईसी ईंजन का उचित विकल्प पाने में लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर फोकस है। नुजेन जेनरेशन मोबिलिटी, हरित, सुरक्षित तथा किफायती होगी। सम्मेलन के विषयों में ई-मोबिलिटी, हाइड्रोमोबिलिटी, कनेक्टेड व्हीकल तथा आईटीएस शामिल किए गए हैं। प्रदर्शनी में वाहन तथा उपकरण बनाने वाली दो सौ से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद प्रस्तुत करेंगी।

सम्मेलन में लाइव टेस्ट डिमॉन्सट्रेशन, प्रशिक्षण सत्र, पैनल, चर्चा तथा टेस्ट ट्रैक डिमॉन्सट्रेशन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में कनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन आईसी ईंजन जैसी भविष्य की वाहन टेक्नोलॉदिखाई जाएगी।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर एनएटीआरआईपी क्रियान्वयन सोसायटी (एनएटीआईएस) का प्रभाग है।